



# राजपत्र, हिमाचल प्रदेश

## हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित

वीरवार, 21 सितम्बर, 2023 / 30 भाद्रपद 1945

हिमाचल प्रदेश सरकार

राज्य कर एवं आबकारी विभाग

अधिसूचना

शिमला-02, 16 सितम्बर, 2023

संख्या: ई0एक्स0एन0-ए (3)-3/2023.—हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश (सड़क द्वारा कतिपय माल के वहन पर) कराधान अधिनियम, 1999 (1999 का अधिनियम संख्यांक 16) की धारा 15 की

129—राजपत्र / 2023-21-09-2023

(7677)

उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, पूर्वोक्त अधिनियम से संलग्न अनुसूची-I में तुरन्त प्रभाव से निम्नलिखित संशोधन करते हैं, अर्थात् :—

### संशोधन

हिमाचल प्रदेश (सड़क द्वारा कतिपय माल के वहन पर) कराधान अधिनियम, 1999 से संलग्न अनुसूची-I में, मद संख्या 17 के सामने स्तम्भ 3 के अन्तर्गत "50 किलोग्राम की प्रत्येक बोरी पर 7.50/— रुपये" शब्दों, अंको और चिन्हों के स्थान पर "50 किलोग्राम की प्रत्येक बोरी पर 11.00/— रुपये" शब्द, अंक और चिन्ह रखे जाएंगे।

आदेश द्वारा,

प्रधान सचिव,  
(राज्य कर एवं आबकारी)।

-----  
[Authoritative English text of this Department Notification No. EXN-A(3)-3/2023, dated, 16-09-2023 as required under clause (3) of the Article 348 of the Constitution of India].

## STATE TAXES AND EXCISE DEPARTMENT

### NOTIFICATION

*Shimla-171002, the 16th September, 2023*

**No. EXN-A (3)-3/2023.**—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 15 of the Himachal Pradesh Taxation (on Certain Goods Carried by Road) Act, 1999 (Act No. 16 of 1999), the Governor, Himachal Pradesh is pleased to make the following amendment in Schedule-I appended to the Act *ibid*, with immediate effect, namely:—

### AMMENDMENT

In Schedule-I appended to the Himachal Pradesh Taxation (on Certain Goods Carried by Road) Act, 1999, in item No. 17, in column 3, for the words, signs and figures "Rs. 7.50 per bag of 50Kgs", the words, signs and figures "Rs. 11.00 per bag of 50 Kgs." shall be substituted.

By order,  
Principal Secretary (ST&E).

## STATE TAXES AND EXCISE DEPARTMENT

### NOTIFICATION

*Shimla-171002, the 16th September, 2023*

**No. EXN-F(10)-17/2022.**—In continuation of this Department's Notifications of even No. dated 3rd March, 2023 and 4th March, 2023, whereby the Himachal Pradesh Sadhbhawana

Legacy Cases Resolution Scheme, 2023 and Procedure for the scheme respectively, were Notified, the Governor of Himachal Pradesh is pleased to launch the 3rd phase of Himachal Pradesh Sadhbhawana Legacy Cases Resolution Scheme, 2023, for three months with effect from 01-10-2023 to 31-12-2023 with the same terms & conditions.

By order,

Sd/-  
(BHARAT KHERA),  
Pr. Secretary (ST&E).

### हिमाचल प्रदेश विधान सभा सचिवालय

अधिसूचना

दिनांक 20 सितम्बर, 2023

संख्या वि०स०-विधायन-विधेयक/1-48/2023.—हिमाचल प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया एवं कार्य संचालन नियमावली, 1973 के नियम-140 के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश निरसन विधेयक, 2023 (2023 का विधेयक संख्यांक 11) जो आज दिनांक 20 सितम्बर, 2023 को हिमाचल प्रदेश विधान सभा में पुरःस्थापित हो चुका है, सर्व-साधारण को सूचनार्थ राजपत्र में मुद्रित करने हेतु प्रेषित किया जाता है।

हस्ताक्षरित/—

सचिव,  
हि० प्र० विधान सभा।

2023 का विधेयक संख्यांक 11

### हिमाचल प्रदेश निरसन विधेयक, 2023

खण्डों का क्रम

खण्ड:

1. संक्षिप्त नाम।
2. कतिपय अधिनियमितियों का निरसन।
3. व्यावृत्तियां।

अनुसूची।

**हिमाचल प्रदेश निरसन विधेयक, 2023**

(विधान सभा में पुरःस्थापित रूप में)

कतिपय अधिनियमितियों का निरसन करने के लिए **विधेयक**।

भारत गणराज्य के चौहत्तरवें वर्ष में हिमाचल प्रदेश विधान सभा द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो:-

1. **संक्षिप्त नाम.**—इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश निरसन अधिनियम, 2023 है।
2. **कतिपय अधिनियमितियों का निरसन.**—अनुसूची में विनिर्दिष्ट अधिनियमितियों का एतद्वारा निरसन किया जाता है।
3. **व्यावृत्तियां.**—इस अधिनियम द्वारा किसी भी अधिनियमिति का निरसन,—
  - (क) किसी अन्य अधिनियमिति, जिसमें निरसित अधिनियमिति लागू सम्मिलित या निर्दिष्ट की गई हो, पर प्रभाव नहीं डालेगा; या
  - (ख) किसी भी अधिकारिता, पद, रुढ़ि, दायित्व, अधिकार, हक, विशेषाधिकार, निर्बन्धन, छूट, प्रथा, पद्धति, प्रक्रिया या अन्य विषय या बात को, जो इस समय विद्यमान या प्रवृत्त नहीं है, पुनः प्रवर्तित या प्रत्यावर्तित नहीं करेगा; या
  - (ग) इस प्रकार निरसित किसी अधिनियमिति के पूर्व प्रवर्तन या तद्धीन सम्यक् रूप से की गई या होने दी गई किसी बात पर प्रभाव नहीं डालेगा; या
  - (घ) इस प्रकार निरसित किसी अधिनियमिति के अधीन अर्जित, प्रोद्भूत या उपगत किसी अधिकार, हक, विशेषाधिकार, बाध्यता या दायित्व पर प्रभाव नहीं डालेगा; या
  - (ङ) इस प्रकार निरसित किसी अधिनियमिति के अधीन, उसके सम्बन्ध में किसी उपचार या कार्रवाई या किसी ऋण, शास्ति, बाध्यता, दायित्व, दावे या मांग के या से किसी निर्मोचन या उन्मोचन या पूर्व मंजूर की गई क्षतिपूर्ति या किसी पूर्व कार्य या बात के सबूत पर प्रभाव नहीं डालेगा; या
  - (च) विधि के किसी भी सिद्धान्त या नियम या स्थापित अधिकारिता, प्ररूप या अभिवचन, पद्धति या प्रक्रिया के अनुक्रम, या विद्यमान प्रथा, रुढ़ि, विशेषाधिकार, निर्बन्धन, छूट, पद या नियुक्ति को इस बात के होते हुए भी कि वे किसी भी प्रकार से एतद्वारा निरसित किसी अधिनियमिति द्वारा, उसमें या उससे, क्रमशः अभिपुष्ट या मान्य या व्युत्पन्न हुए हों, प्रभावित नहीं करेगा; या
  - (छ) इस प्रकार निरसित किसी अधिनियमिति के विरुद्ध किए गए किसी अपराध के सम्बन्ध में उपगत किसी शास्ति, समपहरण या दण्ड पर प्रभाव नहीं डालेगा; या
  - (ज) यथापूर्वोक्त किसी ऐसे अधिकार, विशेषाधिकार, बाध्यता, दायित्व, शास्ति, समपहरण या दण्ड के बारे में किसी अन्वेषण, विधिक कार्यवाही या उपचार पर प्रभाव नहीं डालेगा;

और कोई भी ऐसा अन्वेषण, विधिक कार्यवाही या उपचार संस्थित, चालू या प्रवर्तनशील रखा जा सकेगा और कोई भी ऐसी शास्ति, समपहरण या दण्ड अधिरोपित किया जा सकेगा, मानो कि यह अधिनियम पारित ही नहीं हुआ था।

**अनुसूची**  
(धारा 2 देखें)

वर्ष	अधिनियम संख्या	संक्षिप्त नाम	निरसन का विस्तार
1	2	3	4
1882	15	प्रेसिडेन्सी लघुवाद न्यायालय अधिनियम, 1882	सम्पूर्ण
1884	12	कृषक उधार अधिनियम, 1884	सम्पूर्ण
1887	9	प्रान्तीय लघुवाद न्यायालय अधिनियम, 1887	सम्पूर्ण
		मण्डी लघु वन उपज दोहन एवं नियति अधिनियम, 1997 (विक्रमी सम्वत्) एवं 1941	सम्पूर्ण
		चम्बा लघु वन उपज दोहन एवं नियति अधिनियम, 2003 (विक्रमी सम्वत्)	सम्पूर्ण
1953	7	पंजाब तम्बाकू विक्रेता फीस निरसन अधिनियम, 1953	सम्पूर्ण
1955	6	हिमाचल प्रदेश वैयक्तिक वन अधिनियम, 1954	सम्पूर्ण
1965	17	पंजाब श्रम कल्याण निधि अधिनियम, 1965	सम्पूर्ण
1968	15	पंजाब वृत्ति, व्यापार, आजीविका और नियोजन कराधान (हिमाचल प्रदेश निरसन) अधिनियम, 1968	सम्पूर्ण
1984	22	हिमाचल प्रदेश वन परिरक्षण और वन पर आधारित आवश्यक वस्तु प्रदाय अधिनियम, 1984	सम्पूर्ण
2000	19	हिमाचल प्रदेश निक्षेपकों के हित का (वित्तीय स्थापना में) संरक्षण अधिनियम, 1999	सम्पूर्ण
2003	21	हिमाचल प्रदेश सह-चिकित्सीय परिषद् अधिनियम, 2003	सम्पूर्ण
2008	14	हिमाचल प्रदेश प्रशासनिक अधिकरण (विनिश्चित और लम्बित मामलों तथा आवेदनों का अन्तरण) अधिनियम, 2008	सम्पूर्ण

**उद्देश्यों और कारणों का कथन**

उन अधिनियमितियों को निरसित किया जाना प्रस्तावित है, जिनका महत्व समाप्त हो गया है या जो अप्रचलित और अनावश्यक हैं या जिनका पृथक्, स्वतन्त्र और विशेष अधिनियम के रूप में प्रतिधारण अनावश्यक हो गया है। ऐसे निरसन का मुख्य उद्देश्य स्पष्टता लाने के आशय से कानून की पुस्तक से ऐसी अनावश्यक विधियों को हटाना है। ये विधियाँ या तो असंगत हो गई हैं या अप्रक्रियात्मक हो चुकी हैं और विशेषतया अपना प्रयोजन पूर्ण कर चुकी हैं तथा उनकी उपयोगिता समाप्त हो गई है। इसलिए वांछित उद्देश्य को प्राप्त करने के आशय से विधेयक की अनुसूची में यथाविनिर्दिष्ट तरह अधिनियमों का निरसन करने के लिए हिमाचल प्रदेश निरसन विधेयक, 2023 को लाने का विनिश्चय किया गया है।

यह विधेयक उपर्युक्त उद्देश्यों की पूर्ति के लिए है।

(सुखविन्दर सिंह सुक्खू)  
मुख्य मंत्री।

शिमला :

तारीख : ....., 2023

-----  
वित्तीय ज्ञापन

—शून्य—

-----  
प्रत्यायोजित विधान सम्बन्धी ज्ञापन

—शून्य—

-----  
हिमाचल प्रदेश निरसन विधेयक, 2023

कतिपय अधिनियमितियों का निरसन करने के लिए विधेयक।

(सुखविन्दर सिंह सुक्खू)  
मुख्य मंत्री।

-----  
(शरद कुमार लगवाल)  
सचिव (विधि)।

शिमला :

तारीख : ....., 2023

## BILL NO. 11 OF 2023

## THE HIMACHAL PRADESH REPEALING BILL, 2023

## ARRANGEMENT OF CLAUSES

*Clauses:*

1. Short title.
  2. Repeal of certain enactments.
  3. Savings.
- THE SCHEDULE.

## BILL NO. 11 OF 2023

## THE HIMACHAL PRADESH REPEALING BILL, 2023

(AS INTRODUCED IN THE LEGISLATIVE ASSEMBLY)

A

## BILL

*to repeal certain enactments.*

BE it enacted by the Legislative Assembly of Himachal Pradesh in the Seventy-fourth year of the Republic of India as follows:—

1. **Short title.**—This Act may be called the Himachal Pradesh Repealing Act, 2023.
2. **Repeal of certain enactments.**—The enactments specified in THE SCHEDULE are hereby repealed.
3. **Savings.**—The repeal by this Act of any enactments shall not,—
  - (a) affect any other enactment in which the repealed enactment has been applied, incorporated or referred to; or
  - (b) revive or restore any jurisdiction, office, custom, liability, right, title, privilege, restriction, exemption, usage, practice, procedure or other matter or thing not now existing or in force; or
  - (c) affect the previous operation of any enactments so repealed or anything duly done or suffered thereunder; or
  - (d) affect any right, title, privilege, obligation or liability acquired, accrued or incurred under any enactment so repealed; or
  - (e) affect any remedy or proceeding in respect thereof, or any release or discharge of, or from any debt, penalty, obligation, liability, claim, or demand, or any

indemnity already granted, or the proof of any past act or thing under any enactment so repealed; or

- (f) affect any principle or rule of law, or established jurisdiction, form or course of pleading, practice or procedure, or existing usage, custom, privilege, restriction, exemption, office or appointment, notwithstanding that the same respectively, may have been in any manner affirmed or recognized or derived by, in or from any enactment hereby repealed; or
- (g) affect any penalty, forfeiture or punishment incurred in respect of any offence committed against any enactment so repealed; or
- (h) affect any investigation, legal proceeding or remedy in respect of any such right, privilege, obligation, liability, penalty, forfeiture or punishment, as aforesaid;

and any such investigation, legal proceeding or remedy may be instituted, continued or enforced, and any such penalty, forfeiture or punishment may be imposed as if this Act had not been passed.

### THE SCHEDULE (see Section 2)

Year	Act Number	Short Title	Extent of Repeal
1	2	3	4
1882	15	The Presidency Small Cause Courts Act, 1882.	The Whole
1884	12	The Agriculturists Loans Act, 1884.	The Whole
1887	9	The Provincial Small Cause Courts Act, 1887.	The Whole
-	-	The Mandi Minor Forest Produce Exploitation and Export Act, 1997 (Vikrami Samvat) and 1941.	The Whole
-	-	The Chamba Minor Forest Produce Exploitation and Export Act, 2003 (Vikrami Samvat).	The Whole
1953	7	The Punjab Tobacco Vend Fees (Repealing) Act, 1953.	The Whole
1955	6	The Himachal Pradesh Private Forest Act, 1954.	The Whole
1965	17	The Punjab Labour Welfare Fund Act, 1965.	The Whole
1968	15	The Punjab Professions, Trades, Callings and Employment Taxation (Himachal Pradesh Repealing) Act, 1968.	The Whole
1984	22	The Himachal Pradesh Preservation of Forests and Maintenance of Supplies of Forest Based Essential Commodities Act, 1984.	The Whole

2000	19	The Himachal Pradesh Protection of Interest of Depositors (In Financial Establishment) Act, 1999.	The Whole
2003	21	The Himachal Pradesh Paramedical Council Act, 2003.	The Whole
2008	14	The Himachal Pradesh Administrative Tribunal (Transfer of Decided and Pending Cases and Applications) Act, 2008.	The Whole

### STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS

The enactments which have lost their significance or have become obsolete and redundant or the retention whereof as separate, independent and distinct Act is unnecessary, are proposed to be repealed. The principal object of such repealing is to remove such redundant laws from the statute book to bring in clarity. These laws have become either irrelevant or dysfunctional and importantly have served their purpose and outlived their utility. Thus, in order to achieve the desired objective, it has been decided to bring the Himachal Pradesh Repealing Bill, 2023 to repeal 13 Acts as specified in THE SCHEDULE to the Bill.

This Bill seeks to achieve the aforesaid objectives.

(SUKHVINDER SINGH SUKHU)  
*Chief Minister.*

SHIMLA :  
THE ....., 2023

### FINANCIAL MEMORANDUM

—Nil—

### MEMORANDUM REGARDING DELEGATED LEGISLATION

—Nil—

### THE HIMACHAL PRADESH REPEALING BILL, 2023

A

BILL

*to repeal certain enactments.*

**(SUKHVINDER SINGH SUKHU)**

*Chief Minister.*

**(SHARAD KUMAR LAGWAL)**

*Secretary (Law).*

SHIMLA :

THE ....., 2023

हिमाचल प्रदेश विधान सभा सचिवालय

अधिसूचना

दिनांक 20 सितम्बर, 2023

**संख्या वि०स०-विधायन-विधेयक/1-47/2023.**—हिमाचल प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया एवं कार्य संचालन नियमावली, 1973 के नियम-140 के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश कृषि, औद्योगिकी और वानिकी विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2023 (2023 का विधेयक संख्यांक 14) जो आज दिनांक 20 सितम्बर, 2023 को हिमाचल प्रदेश विधान सभा में पुरःस्थापित हो चुका है, सर्व-साधारण को सूचनार्थ राजपत्र में मुद्रित करने हेतु प्रेषित किया जाता है।

हस्ताक्षरित/—

सचिव,

हि० प्र० विधान सभा।

**हिमाचल प्रदेश कृषि, औद्यानिकी और वानिकी विश्वविद्यालय (संशोधन)  
विधेयक, 2023**

खण्डों का क्रम

खण्ड:

1. संक्षिप्त नाम।
2. धारा 2 का संशोधन।
3. धारा 23 का संशोधन।
4. धारा 24 का संशोधन।
5. धारा 55क का अन्तःस्थापन।

2023 का विधेयक संख्यांक 14

**हिमाचल प्रदेश कृषि, औद्यानिकी और वानिकी विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2023**

(विधान सभा में पुरःस्थापित रूप में )

हिमाचल प्रदेश कृषि, औद्यानिकी और वानिकी विश्वविद्यालय अधिनियम, 1986 (1987 का अधिनियम संख्यांक 4) का और संशोधन करने के लिए **विधेयक**।

भारत गणराज्य के चौहत्तरवें वर्ष में हिमाचल प्रदेश विधान सभा द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो:-

**1. संक्षिप्त नाम.**—इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश कृषि, औद्यानिकी और वानिकी विश्वविद्यालय (संशोधन) अधिनियम, 2023 है।

**2. धारा 2 का संशोधन.**—हिमाचल प्रदेश कृषि, औद्यानिकी और वानिकी विश्वविद्यालय अधिनियम, 1986 (जिसे इसमें इसके पश्चात् "मूल अधिनियम" कहा गया है) की धारा 2 के खण्ड (प) में "बनाए गए" शब्दों के पश्चात् "नियमों," शब्द और चिन्ह अन्तःस्थापित किए जाएंगे।

**3. धारा 23 का संशोधन.**—मूल अधिनियम की धारा 23 की उपधारा (4) में "कुलाधिपति" शब्द के पश्चात् "सरकार की सहायता और सलाह पर" शब्द अन्तःस्थापित किए जाएंगे।

**4. धारा 24 का संशोधन.**—मूल अधिनियम की धारा 24 में,—

(i) उपधारा (1) के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात्:—

"कुलपति विश्वविद्यालय का पूर्णकालिक अधिकारी होगा, जिसकी नियुक्ति कुलाधिपति द्वारा सरकार की सहायता और सलाह पर ऐसी रीति में की जाएगी, जैसी नियमों द्वारा विहित की जाए।"; और

(ii) उपधारा (2) का लोप किया जाएगा।

**5. धारा 55क का अन्तःस्थापन.**—मूल अधिनियम की धारा 55 के पश्चात् निम्नलिखित धारा अन्तःस्थापित की जाएगी, अर्थात्:—

**"55—क नियम बनाने की शक्ति.—**(1) राज्य सरकार, इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिए राजपत्र (ई—गजट), हिमाचल प्रदेश में, अधिसूचना द्वारा नियम बना सकेगी।

- (2) इस अधिनियम के अधीन बनाया गया प्रत्येक नियम, बनाए जाने के पश्चात् यथाशक्यशीघ्र, विधान सभा के समक्ष, जब वह कुल दस दिन की अवधि से अन्यून सत्र में हों, के लिए रखा जाएगा। यह अवधि एक सत्र में अथवा दो या दो से अधिक अनुक्रमिक सत्रों में पूरी हो सकेगी और यदि सत्र के अवसान के पूर्व जिसमें यह इस तरह रखा गया था या शीघ्र बाद के सत्र में, विधान सभा में कोई उपांतरण करती है या विनिश्चय करती है कि नियम नहीं बनाया जाना चाहिए तो नियम उसके पश्चात् केवल ऐसे उपान्तरित रूप में, यथास्थिति, प्रभावी होगा, या निष्प्रभाव हो जाएगा, किन्तु नियम के ऐसे परिवर्तित या निष्प्रभाव होने से उसके अधीन पहले की गई किसी बात की विधिमान्यता पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा।"

-----

### उद्देश्यों और कारणों का कथन

हिमाचल प्रदेश कृषि, औद्यानिकी और वानिकी विश्वविद्यालय अधिनियम, 1986 को हिमाचल प्रदेश के दो विश्वविद्यालयों नामतः चौधरी सरवण कुमार हिमाचल प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय, पालमपुर और डा० यशवन्त सिंह परमार औद्यानिकी और वानिकी विश्वविद्यालय सोलन में कृषि, औद्यानिकी और वानिकी के क्षेत्रों में अध्ययन, अनुसंधान और विस्तार शिक्षा के समरूप मानदंडों के प्रवर्तन हेतु तथा उक्त विश्वविद्यालयों में कर्मचारियों की वित्तीय व्यवस्थाओं तथा सेवा शर्तों में एकरूपता लाने के लिए भी समुचित उपबंध करने हेतु अधिनियमित किया गया था।

तथापि, हिमाचल प्रदेश कृषि, औद्यानिकी और वानिकी विश्वविद्यालय अधिनियम, 1986 की धारा 2, 23 और 24 में विश्वविद्यालयों में कुलपति की नियुक्ति हेतु लोकतान्त्रिक रूप से निर्वाचित सरकार की कोई भूमिका नहीं है, यद्यपि इन संस्थाओं का वित्तपोषण अनुदान के रूप में राज्य—बजट द्वारा किया जाता है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 2020 युवा राष्ट्र की अपेक्षाओं की पूर्ति हेतु गुणात्मक परिवर्तन लाने और हमारी शिक्षा प्रणाली को वैश्विक चुनौतियों का सामना करने के लिए व्यापक रूपरेखा की व्यवस्था करती है। इसके लिए हमें ऐसे कुलपतियों की आवश्यकता है जो बहु—शिक्षा शाखाओं वाली संस्थाओं जो संवैधानिक मूल्यों और राष्ट्र निर्माण के प्रति प्रतिबद्ध हों, का सृजन करने में सक्षम हैं।

यह पाया गया है कि कुलपति के चयन से संबंधित विद्यमान उपबंध निर्बंधनात्मक हैं, क्योंकि ये लोगों की अपेक्षाओं का संज्ञान नहीं लेते तथा लोकतांत्रिक सरकार को उच्चतर शिक्षा की संस्थाओं को सही रूप प्रदान करने के इसके अधिकार का प्रयोग करने हेतु अनुज्ञात नहीं करते। हमारे जैसे लोकतांत्रिक राष्ट्र में, उच्चतर शिक्षा के संस्थानों की अध्यक्षता अवश्यमेव विख्यात लोगों द्वारा की जानी चाहिए, जो विश्वस्तर के संस्थानों और भारत के संविधान में उल्लिखित मूल्यों का परिवर्धन और सृजन कर सकें। अतः अधिनियम की धारा 2, 23 और 24 का संशोधन किया जाना आवश्यक है। इसके अतिरिक्त, अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने हेतु राज्य सरकार को नियम बनाने हेतु सशक्त करने के लिए एक नई धारा 55—क को अन्तःस्थापित किया जा रहा है। इससे उपरोक्त अधिनियम में संशोधन करना आवश्यक हो गया है।

यह विधेयक उपरोक्त उद्देश्यों की पूर्ति के लिए है।

(चन्द्र कुमार)  
प्रभारी मन्त्री।

शिमला

तारीख 2023

## वित्तीय ज्ञापन

—शून्य—

## प्रत्यायोजित विधान सम्बन्धी ज्ञापन

विधेयक का खण्ड 4 और 5 राज्य सरकार को इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने हेतु नियम बनाने के लिए सशक्त करता है। शक्तियों का प्रस्तावित प्रत्यायोजन अनिवार्य और सामान्य स्वरूप का है।

हिमाचल प्रदेश कृषि, औद्यानिकी और वानिकी विश्वविद्यालय (संशोधन)  
विधेयक, 2023

(विधान सभा में पुरःस्थापित रूप में )

हिमाचल प्रदेश कृषि, औद्यानिकी और वानिकी विश्वविद्यालय अधिनियम, 1986 (1987 का अधिनियम संख्यांक 4) का और संशोधन करने के लिए विधेयक।

(चन्द्र कुमार)  
प्रभारी मन्त्री।(शरद कुमार लगवाल)  
सचिव (विधि)।

शिमला:

तारीख, 2023

## AUTHORITATIVE ENGLISH TEXT

BILL NO. 14 OF 2023

THE HIMACHAL PRADESH UNIVERSITIES OF AGRICULTURE, HORTICULTURE  
AND FORESTRY (AMENDMENT) BILL, 2023

## ARRANGEMENT OF CLAUSES

Clauses:

1. Short title.
2. Amendment of section 2.
3. Amendment of section 23.
4. Amendment of section 24.
5. Insertion of section 55-A.

**THE HIMACHAL PRADESH UNIVERSITIES OF AGRICULTURE, HORTICULTURE  
AND FORESTRY (AMENDMENT) BILL, 2023**

(As INTRODUCED IN THE LEGISLATIVE ASSEMBLY)

A

BILL

*further to amend the Himachal Pradesh Universities of Agriculture, Horticulture and Forestry Act, 1986 (Act No. 4 of 1987).*

BE it enacted by the Legislative Assembly of Himachal Pradesh in the Seventy-fourth Year of the Republic of India as follows:—

**1. Short title.**—This Act may be called the Himachal Pradesh Universities of Agriculture, Horticulture and Forestry (Amendment) Act, 2023.

**2. Amendment of section 2.**—In section 2 of the Himachal Pradesh Universities of Agriculture, Horticulture and Forestry Act, 1986 (hereinafter referred to as the “principal Act”), in clause (u), after the words “prescribed by”, the words and sign “the Rules,” shall be inserted.

**3. Amendment of section 23.**—In section 23 of the principal Act, in sub-section (4), after the words “The Chancellor”, the signs and the words, “on the aid and advice of the Government,” shall be inserted.

**4. Amendment of section 24.**—In section 24 of the principal Act,—

(i) for sub-section (1), the following shall be substituted, namely:—

“The Vice-Chancellor shall be a whole time officer of the University, who shall be appointed by the Chancellor, on the aid and advice of the Government, in the manner as may be prescribed by the rules.”; and

(ii) sub- section (2) shall be omitted.

**5. Insertion of section 55-A .**—After section 55 of the principal Act, the following section shall be inserted, namely:—

**“55-A. Power to make rules.**—(1) The State Government may, by notification in the Rajpatra (e-Gazette), Himachal Pradesh, make rules for carrying out the purposes of this Act.

(2) Every rule made under this Act, shall be laid, as soon as may be after it is made, before the Legislative Assembly, while it is in session, for a total period of not less than ten days which may be comprised in one session or in two or more successive sessions, and if, before the expiry of the session in which it is so laid or the session immediately following, the Assembly makes any modification in the rule or decides that the rule should not be made, the rule shall, thereafter, have effect only in such modified form or be of no effect, as the case may be, so, however, that any such modification or annulment shall be without prejudice to the validity of anything previously done under that rule.”.

**STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS**

The Himachal Pradesh Universities of Agriculture, Horticulture and Forestry Act, 1986 was enacted to make suitable provisions for enforcing uniform standards of teaching, research and extension education in the fields of agriculture, horticulture and forestry in the two Universities of Himachal Pradesh namely the Chaudhary Sarwan Kumar Himachal Pradesh Krishi Vishvavidyalaya at Palampur and Dr. Yashwant Singh Parmar University of Horticulture and Forestry at Solan, as also, for having uniformity in financial arrangements and in service conditions of the employees in the said Universities.

However, in sections 2, 23, 24 of the Himachal Pradesh Universities of Agriculture, Horticulture and Forestry Act, 1986 there was no role of the democratically elected Government for appointment of Vice-Chancellor in the Universities even though the State Government issues Grant-in-Aid to these institutions. The National Education Policy, 2020 lays the broad framework to bring about the qualitative changes to meet the aspirations of a young nation and to align our education system to meet global changes. For this we need to have Vice-Chancellors who are capable to create multi-disciplinary institutions that are committed to constitutional values and nation building.

It is found that the existing provisions regarding selection of the Vice-Chancellor are restrictive as these do not take into account the aspirations of the people and do not allow democratic Government to exercise its right to shape the institutions of higher learning. In democratic nation like ours, the institutions of higher learning must be headed by the people of eminence who can create world class institutions that promote and foster values enshrined in the Constitution of India. Therefore, sections 2, 23, 24 of the Act need to be amended. Further, a new section 55-A empowering the State Government to make rules for carrying out the purposes of the Act is being inserted. This has necessitated amendments in the Act *ibid*.

This Bill seeks to achieve the aforesaid objectives.

**(CHANDER KUMAR)**

*Minister-in-Charge.*

SHIMLA:

THE , 2023.

**FINANCIAL MEMORANDUM**

—NIL—

**MEMORANDUM REGARDING DELEGATED LEGISLATION**

Clauses 4 and 5 of the Bill seek to empower the State Government to make rules for carrying out the purposes of this Act. The proposed delegation of power is essential and normal in character.

**THE HIMACHAL PRADESH UNIVERSITIES OF AGRICULTURE, HORTICULTURE  
AND FORESTRY (AMENDMENT) BILL, 2023**

(AS INTRODUCED IN THE LEGISLATIVE ASSEMBLY)

A

BILL

*further to amend the Himachal Pradesh Universities of Agriculture, Horticulture and Forestry Act, 1986 (Act No.4 of 1987).*

**(CHANDER KUMAR)**  
*Minister-in-Charge.*

**(SHARAD KUMAR LAGWAL)**  
*Secretary (Law).*

SHIMLA:  
THE , 2023.

ब अदालत तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी नादौन, तहसील नादौन,  
जिला हमीरपुर (हि0प्र0)

श्री ओम प्रकाश पुत्र श्री जगरनाथ, निवासी महाल भगवानी, मौजा सपडोह, तहसील नादौन, जिला हमीरपुर (हि0प्र0)।

बनाम

आम जनता

विषय.—प्रार्थना-पत्र बराये मकफूद-उल-खबरी बारे।

श्री ओम प्रकाश पुत्र श्री जगरनाथ, निवासी महाल भगवानी, मौजा सपडोह, तहसील नादौन, जिला हमीरपुर (हि0प्र0) ने दिनांक 17-03-2023 को इस अदालत में एक प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत किया है कि उसकी माता श्रीमती रुक्मणी देवी 20-21 सालों से लापता है। प्रार्थी ने अपनी माता की गुमशुदगी की FIR भी करवा रखी है। प्रार्थी अब अपनी माता का इन्तकाल दर्ज करवाना चाहता है।

अतः इस गजट इश्तहार द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि किसी व्यक्ति को उपरोक्त प्रार्थी की माता के इन्तकाल को दर्ज करने बारे कोई उजर एवं एतराज हो तो वह असातन या वकालतन

तारीख पेशी 24-09-2023 को सुबह 11.00 बजे मुकाम नादौन हाजिर अदालत होकर अपना उजर पेश कर सकता है। तारीख पेशी के बाद किसी किस्म का एतराज काबिले समायत न होगा तथा प्रार्थी के प्रार्थना-पत्र बारे आवश्यक आदेश पारित कर दिये जायेंगे।

यह इश्तहार मोहर अदालत व मेरे हस्ताक्षर से आज दिनांक 01-09-2023 को जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित /—  
तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी,  
नादौन, जिला हमीरपुर (हि0प्र0)।

-----

**In the Court of Dr. Rohit Sharma, Sub-Divisional Magistrate Barsar, District Hamirpur (H.P.) Exercising the Powers of Marriage Officer under Special Marriage Act, 1954**

In the matter of :

1. Mr. Subhash Chand age 37 years s/o Sh. Roshan Lal, r/o Village Adhrin, P.O. Kaswar, Tehsil Barsar, District Hamirpur (H.P.).

2. Ms. Ganga Shrestha age 32 years d/o Sh. Krishan Bahadur Shrestha, r/o Kharewada Pixem Dongri, Nagar Puja Hotel, Wasco-Da-Gama, South Goa .. Applicants.

*Versus*

General Public

Subject.— Notice of Marriage

Mr. Subhash Chand and Ms. Ganga Shrestha have filed an application u/s 15 of the Special Marriage Act, 1954 alongwith affidavits and supporting documents in the court of undersigned, in which they have stated that they have solemnized their marriage on dated 31-08-2023 as per Hindu rites and customs at sen Bhagat Mahasabha Mandir, Village & P.O. Mehre, Tehsil Barsar, District Hamirpur (H.P.).

Therefore, the general public is hereby informed through this notice that if any person having any objection regarding this marriage, may file his/her objections personally or in writing before this court on or before 11-10-2023. In case no objection is received by 11-10-2023, it will be presumed that there is no objection to the registration of the above said marriage and the same will be registered accordingly.

Issued under my hand and seal of the court on 08-09-2023.

Seal.

Sd/-  
Marriage Officer-cum-SDM,  
Sub-Division Barsar, District Hamirpur (H.P.).

**ब अदालत तहसीलदार एवम् कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील खुण्डियां,  
जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)**

केस नं० : 16/B/T/ 2023

तारीख पेशी : 09-10-2023

पवना कुमारी पुत्री श्री प्रताप चन्द, निवासी गांव चौकी, डाकघर टिहरी, तहसील खुण्डियां, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश।

बनाम

आम जनता

उनवान मुकद्दमा.—जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 के तहत जन्म तिथि पंजीकरण करने।

नोटिस बनाम आम जनता।

प्रार्थिया पवना कुमारी पुत्री श्री प्रताप चन्द, निवासी गांव चौकी, डाकघर टिहरी, तहसील खुण्डियां, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश ने स्वयं उपस्थित होकर प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत किया है कि उसका जन्म दिनांक 09-09-1974 को हुआ है परन्तु गलती से ग्राम पंचायत टिहरी के अभिलेख में उसकी जन्म तिथि दर्ज नहीं हुई है जिसका ग्राम पंचायत टिहरी के अभिलेख में दर्ज किया जाना अनिवार्य है।

अतः सर्वसाधारण को सुनवाई हेतु बजरिये इश्तहार व मुन्त्री मुनादी द्वारा सूचित किया जाता है कि इस सम्बन्ध में किसी प्रकार का उजर/एतराज हो तो वह दिनांक 09-10-2023 को असालतन व वकालतन पेश होकर अपना एतराज दर्ज करवा सकता है। उसके उपरान्त कोई भी उजर/एतराज जेरे समायत न होगा तथा श्रीमती पवना कुमारी पुत्री श्री प्रताप चन्द, निवासी गांव चौकी, डाकघर टिहरी की जन्म तिथि दिनांक 09-09-1974 जेरे धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 के तहत ग्राम पंचायत टिहरी के अभिलेख में दर्ज करने के आदेश पारित कर दिये जायेंगे।

आज दिनांक 08-09-2023 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/—

तहसीलदार एवम् कार्यकारी दण्डाधिकारी,  
तहसील खुण्डियां, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)।

ब अदालत नायब तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, भवारना,  
जिला कांगड़ा (हि0प्र0)

मुकद्दमा नं० :  
/ 2023

किस्म मुकद्दमा :  
तकसीम

खाता नम्बर :  
71

तारीख पेशी :  
10-10-2023

1. धनश्याम पुत्र सन्त राम पुत्र कांशी राम, निवासी महाल ओडर, उप-तहसील भवारना, जिला कांगड़ा (हि0प्र0) प्रार्थी।

बनाम

1. कुलभूषण पुत्र टेक चन्द, 2. संजीव सूद पुत्र शशी किरण, 3. विकास सूद पुत्र शशी किरण, 4. नीतू पुत्री रवि किरण, 5. चिराग सूद पुत्र अभिनाथ सूद, 6. तपीन सूद पुत्र सुरेन्द्र, 7. तरु पुत्री सुरेन्द्र, 8. नरेन्द्र पुत्र सागर चन्द, 9. विरेन्द्र पुत्र सागर चन्द, 10. राजेश्वरी देवी पत्नी स्व० सागर चन्द, 11. कामनी पुत्री ठाकरी देवी, 12. रीता पुत्री जयन्ती, 13. अनिता पुत्री जयन्ती, 14. सुधा पुत्री जयन्ती, 15. रजनी पुत्री जयन्ती, 16. ईश्वर दास पुत्र संजय डोगरा, 17. सुरेश कुमार पुत्र संजय डोगरा, 18. अशोक कुमार पुत्र संजय डोगरा, 19. लोकनाथ पुत्र संजय डोगरा, 20. करण पुत्र संजय डोगरा, 21. रिचा पुत्री संजय डोगरा, 22. कार्तिक पुत्र विवेक डोगरा, 23. अक्षमा पुत्री विवेक डोगरा, 24. अनामिका पुत्री कुलदीप कुमार, 25. जयन्ती देवी पत्नी स्व० नवीन चन्द, 26. कामनी देवी पुत्री ठाकरी देवी, 27. प्रताप पुत्र सरला देवी, 28. गायत्री देवी पुत्री सन्त राम, 29. भुवनेश कुमार पुत्र सन्त राम, 30. कुशम पत्नी जोगराज, 31. कुशम डोगरा पत्नी सुरेन्द्र कुमार निवासीगण महाल, मौजा व उप-तहसील भवारना, जिला कांगड़ा (हि०प्र०) प्रतिवादीगण।

विषय.—प्रार्थना—पत्र तकसीम हुकमन अधीन धारा 123 हि०प्र० भू-राजस्व अधिनियम, 1954 भूमि खाता नं० 71, खतौनी नं० 103, खसरा कित्ता 03, रकबा तादादी 00—21—64 हैक्ट० अनुसार जमाबन्दी 2014—2015 महाल भवारना, उप-तहसील भवारना, जिला कांगड़ा (हि०प्र०)।

उपरोक्त मुकद्दमा तकसीम इस न्यायालय में विचाराधीन है। उपरोक्त प्रतिवादीगण को कई बार समन जारी किए गए परन्तु अदालत की सन्तुष्टि हेतु यह सिद्ध हो चुका है कि उपरोक्त प्रतिवादीगण को साधारण तरीके से तामील होना असम्भव है। अतः अब इस इशतहार राजपत्र व मुस्त्री मुनादी व चस्पांगी के माध्यम से उपरोक्त प्रतिवादीगण को सूचित किया जाता है कि इस तकसीम मुकद्दमा की पैरवी हेतु वह दिनांक 10—10—2023 को अधोहस्ताक्षरी की अदालत में असालतन या वकालतन हाजिर आएँ अन्यथा गैरहाजिरी की सूरत में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।

आज दिनांक 29—08—2023 को हस्ताक्षर व मोहर सहित जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/—  
नायब तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी,  
भवारना, जिला कांगड़ा (हि०प्र०)।

**ब अदालत नायब तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, थुरल, जिला कांगड़ा (हि०प्र०)**

मुकद्दमा नं० : 12/2023

तारीख पेशी : 12—10—2023

किस्म प्रकरण : जन्म पंजीकरण

श्रीमती अमरजीत कुमारी पुत्री जम्बू राम, निवासी गांव नागनं, डा० मुण्डी, तहसील थुरल, ग्राम पंचायत मुण्डी, जिला कांगड़ा (हि०प्र०) प्रार्थिया।

बनाम

आम जनता

प्रतिवादी।

विषय.—जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 की धारा 13(3) के तहत जन्म पंजीकरण हेतु प्रार्थना—पत्र।

श्रीमती अमरजीत कुमारी पुत्री जम्बू राम, निवासी गांव नागनं, डा० मुण्डी, तहसील थुरल, ग्राम पंचायत मुण्डी, जिला कांगड़ा (हि०प्र०) ने इस अदालत में प्रार्थना—पत्र मय ब्यान हल्फी पेश करते हुए आवेदन किया है

कि उसका जन्म दिनांक 06-03-1971 को गांव नागन, डाकघर मुण्डी, तहसील थुरल, ग्राम पंचायत मुण्डी जिला कांगड़ा में हुआ है परन्तु अज्ञानतावश उसके जन्म का पंजीकरण स्थानीय ग्राम पंचायत के अभिलेख में दर्ज न करवाया गया है। अतः प्रार्थिया इस न्यायालय के माध्यम से अपने जन्म का पंजीकरण करने का आदेश ग्राम पंचायत मुण्डी को जारी करवाना चाहती है।

अतः प्रार्थिया का आवेदन स्वीकार करते हुए इस इशतहार मुस्त्री मुनादी द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति या संस्था को उपरोक्त की जन्म तिथि 06-03-1971 के पंजीकरण बारे कोई उजर एवं एतराज हो तो वह असालतन या वकालतन तारीख पेशी 12-10-2023 को हाजिर अदालत होकर अपना उजर व एतराज पेश कर सकता है। बाद तारीख पेशी किसी किस्म का उजर एवं एतराज नहीं सुना जावेगा व उपरोक्त श्रीमती अमरजीत कुमारी पुत्री जम्बू राम की जन्म तिथि को पंजीकृत करने का आदेश उप-स्थानीय पंजीकार, जन्म व मृत्यु, ग्राम पंचायत मुण्डी को पारित कर दिया जाएगा।

यह इशतहार मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से आज दिनांक 12-09-2023 को जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित /—  
नायब तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी  
थुरल, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।

**ब अदालत नायब तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, थुरल, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)**

मुकद्दमा नं0 : 13/2023

तारीख पेशी : 12-10-2023

किस्म प्रकरण : जन्म पंजीकरण

श्रीमती ललिता देवी पुत्री जम्बू राम, निवासी गांव नागन, डा0 मुण्डी, तहसील थुरल, ग्राम पंचायत मुण्डी, जिला कांगड़ा (हि0प्र0) प्रार्थिया।

बनाम

आम जनता

प्रतिवादी।

विषय.—जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 की धारा 13(3) के तहत जन्म पंजीकरण हेतु प्रार्थना-पत्र।

श्रीमती ललिता देवी पुत्री जम्बू राम, निवासी गांव नागन, डा0 मुण्डी, तहसील थुरल, ग्राम पंचायत मुण्डी, जिला कांगड़ा (हि0प्र0) ने इस अदालत में प्रार्थना-पत्र मय ब्यान हल्फी पेश करते हुए आवेदन किया है कि उसका जन्म दिनांक 07-04-1970 को गांव नागन, डाकघर मुण्डी, तहसील थुरल, ग्राम पंचायत मुण्डी, जिला कांगड़ा में हुआ है परन्तु अज्ञानतावश उसके जन्म का पंजीकरण स्थानीय ग्राम पंचायत के अभिलेख में दर्ज न करवाया गया है। अतः प्रार्थिया इस न्यायालय के माध्यम से अपने जन्म का पंजीकरण करने का आदेश ग्राम पंचायत मुण्डी को जारी करवाना चाहती है।

अतः प्रार्थिया का आवेदन स्वीकार करते हुए इस इशतहार मुस्त्री मुनादी द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति या संस्था को उपरोक्त की जन्म तिथि 07-04-1970 के पंजीकरण बारे कोई उजर एवं एतराज हो तो वह असालतन या वकालतन तारीख पेशी 12-10-2023 को हाजिर अदालत होकर अपना उजर व एतराज पेश कर सकता है। बाद तारीख पेशी किसी किस्म का उजर एवं एतराज नहीं

सुना जावेगा व उपरोक्त श्रीमती ललिता देवी पुत्री जम्बू राम की जन्म तिथि को पंजीकृत करने का आदेश उप-स्थानीय पंजीकार, जन्म व मृत्यु, ग्राम पंचायत मुण्डी को पारित कर दिया जाएगा।

यह इशतहार मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से आज दिनांक 12-09-2023 को जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/—  
नायब तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी  
थुरल, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।

**ब अदालत नायब तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, थुरल, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)**

मुकद्दमा नं० : 11 / 2023

तारीख पेशी : 12-10-2023

किस्म प्रकरण : जन्म पंजीकरण

श्रीमती मन्जु देवी पुत्री जम्बू राम, निवासी गांव नागनं, डा0 मुण्डी, तहसील थुरल, ग्राम पंचायत मुण्डी, जिला कांगड़ा (हि0प्र0) प्रार्थिया।

बनाम

आम जनता

प्रतिवादी।

विषय.—जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 की धारा 13(3) के तहत जन्म पंजीकरण हेतु प्रार्थना-पत्र।

श्रीमती मन्जु देवी पुत्री जम्बू राम, निवासी गांव नागनं, डा0 मुण्डी, तहसील थुरल, ग्राम पंचायत मुण्डी, जिला कांगड़ा (हि0प्र0) ने इस अदालत में प्रार्थना-पत्र मय ब्यान हल्फी पेश करते हुए आवेदन किया है कि उसका जन्म दिनांक 07-07-1975 को गांव नागनं, डाकघर मुण्डी, तहसील थुरल, ग्राम पंचायत मुण्डी, जिला कांगड़ा में हुआ है परन्तु अज्ञानतावश उसके जन्म का पंजीकरण स्थानीय ग्राम पंचायत के अभिलेख में दर्ज न करवाया गया है। अतः प्रार्थिया इस न्यायालय के माध्यम से अपने जन्म का पंजीकरण करने का आदेश ग्राम पंचायत मुण्डी को जारी करवाना चाहती है।

अतः प्रार्थिया का आवेदन स्वीकार करते हुए इस इशतहार मुस्त्री मुनादी द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति या संस्था को उपरोक्त की जन्म तिथि 07-07-1975 के पंजीकरण बारे कोई उजर एवं एतराज हो तो वह असालतन या वकालतन तारीख पेशी 12-10-2023 को हाजिर अदालत होकर अपना उजर व एतराज पेश कर सकता है। बाद तारीख पेशी किसी किस्म का उजर एवं एतराज नहीं सुना जावेगा व उपरोक्त श्रीमती मन्जु देवी पुत्री जम्बू राम की जन्म तिथि को पंजीकृत करने का आदेश उप-स्थानीय पंजीकार, जन्म व मृत्यु, ग्राम पंचायत मुण्डी को पारित कर दिया जाएगा।

यह इशतहार मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से आज दिनांक 12-09-2023 को जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/—  
नायब तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी  
थुरल, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।

ब अदालत सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील धर्मशाला,  
जिला कांगड़ा (हि0प्र0)

मुकद्दमा नं० :

Smt. Raj Kumari d/o Late Ghinder Ram, r/o V.P.O. Panther (Passu), Tehsil Dharamshala, District Kangra (H.P.) at present wd/o Sh. Parkash Chand s/o Megh Raj, r/o Ward No. 6, Shakti Gali, Durga Bazar, Tehsil & District Kangra (H.P.).

बनाम

आम जनता

विषय.—प्रार्थना-पत्र जेरे धारा 13(3) हिमाचल प्रदेश जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.

Smt. Raj Kumari d/o Late Ghinder Ram, r/o V.P.O. Panther (Passu), Tehsil Dharamshala, District Kangra (H.P.) at present wd/o Sh. Parkash Chand s/o Megh Raj, r/o Ward No. 6, Shakti Gali, Durga Bazar, Tehsil & District Kangra (H.P.) ने इस अदालत में शपथ-पत्र सहित मुकद्दमा दायर किया है कि उसकी Self Raj Kumari d/o Ghinder Ram की जन्म तिथि 10-12-1953 है परन्तु एम0 सी0 धर्मशाला/ग्राम पंचायत में जन्म तिथि पंजीकृत न है। अतः इसे पंजीकृत किये जाने के आदेश दिये जायें। इस नोटिस के द्वारा समस्त जनता को तथा सम्बन्धित सम्बन्धियों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी को उपरोक्त Raj Kumari की जन्म तिथि पंजीकृत किये जाने बारे कोई एतराज हो तो वह हमारी अदालत में दिनांक 23-10-2023 को असालतन या वकालतन हाजिर होकर पेश कर सकता है अन्यथा मुताबिक शपथ-पत्र जन्म तिथि पंजीकृत किये जाने बारे आदेश पारित कर दिये जायेंगे।

आज दिनांक 13-09-2023 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी किया गया।

मोहर।

हस्ताक्षरित/—

सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी,  
तहसील धर्मशाला, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।

ब अदालत सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील धर्मशाला,  
जिला कांगड़ा (हि0प्र0)

मुकद्दमा नं० :

Rajesh Guleri s/o Late Sh. Piyush Guleri, r/o Housing Board Colony Chilghari, Tehsil Dharamshala, District Kangra (H.P.).

बनाम

आम जनता

विषय.—प्रार्थना-पत्र जेरे धारा 13(3) हिमाचल प्रदेश जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.

Rajesh Guleri s/o Late Sh. Piyush Guleri, r/o Housing Board Colony Chilghari, Tehsil Dharamshala, District Kangra (H.P.) ने इस अदालत में शपथ-पत्र सहित मुकद्दमा दायर किया है कि उसके son Sarvaansh Guleri की जन्म तिथि 28-08-2006 है परन्तु एम0 सी0 धर्मशाला/ग्राम पंचायत में जन्म तिथि पंजीकृत न है। अतः इसे पंजीकृत किये जाने के आदेश दिये जायें। इस नोटिस के द्वारा समस्त जनता को तथा सम्बन्धित सम्बन्धियों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी को उपरोक्त Sarvaansh Guleri की जन्म तिथि पंजीकृत किये जाने बारे कोई एतराज हो तो वह हमारी अदालत में दिनांक 11-10-2023 को असालतन या वकालतन हाजिर होकर पेश कर सकता है अन्यथा मुताबिक शपथ-पत्र जन्म तिथि पंजीकृत किये जाने बारे आदेश पारित कर दिये जायेंगे। उसके बाद कोई भी उजर/एतराज काबिले समायत न होगा।

आज दिनांक 11-09-2023 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी किया गया।

मोहर।

हस्ताक्षरित/—

सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी,  
तहसील धर्मशाला, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।

### नाम परिवर्तन

मैं, रजनी देवी पत्नी रती राम, निवासी गांव सुजी, डा0 जाबली, तहसील कसौली, जिला सोलन (हि0प्र0) ने अपना नाम मीना कुमारी से बदलकर रजनी देवी पत्नी रती राम रख लिया है।

रजनी देवी  
पत्नी रती राम,  
निवासी गांव सुजी, डा0 जाबली,  
तहसील कसौली, जिला सोलन (हि0प्र0)।

### CHANGE OF NAME

I, Kamal Kant s/o Lt. Sh. Balak Ram, r/o Bhurak, P.O. Khagna, Tehsil Chopal, Distt. Shimla (H.P.) declare that my son name is Kushagra wrongly entered in the Aadhar Card. Whereas Reyansh Sharma is entered in the birth certificate and school records. My son correct name is Reyansh Sharma. Please all concerned note.

KAMAL KANT  
s/o Lt. Sh. Balak Ram,  
r/o Bhurak, P.O. Khagna,  
Tehsil Chopal, Distt. Shimla (H.P.).

